



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155 ]  
No. 155]नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2000/आषाढ़ 26, 1922  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2000/ASADHA 26, 1922

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2000

अंतिम निष्कर्ष

विषय : पौलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, साऊदी अरब, रूस, ईरान, अमरीका तथा यूरोपीय संघ से ओक्सो एल्कोहल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच-अंतिम निष्कर्ष

सं. 15/1/99-डी जी ए डी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

## क.पद्धति

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

(i) ओक्सो एल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोशिएशन जिसमें शामिल हैं मै० इंडो निशान ओक्सो कैमिकल इंडस्ट्रीज लि०, मुंबई, नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लि०, मुंबई तथा आंश्रा पैट्रो कैमिकल लि०, हैदराबाद द्वारा दायर याचिका के आधार पर और सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार पौलैंड दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया साऊदी अरब, रूस, ईरान, अमरीका तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) से भारत में ओक्सो एलकोहल के होने वाले आयातों के विरुद्ध दिनांक 29.7.99 की अधिसूचना सं० 15/1/99-डीजीएडी के द्वारा जांच शुरू की गयी थी ।

(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 3.12.99 की अधिसूचना द्वारा पौलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, साऊदी अरब, रूस, ईरान, अमरीका तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) से ओक्सो एल्कोहल के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया था तथा हितबद्ध पार्टियों से इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था ।

(iii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिनसे इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ;

(iv) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशो/क्षेत्रों के दूतावासों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने अपने विचार उपर्युक्त पैरा (ii)(iii) में यथानिर्धारित समय सीमा के भीतर भेजने की सलाह दी जाए ।

(v) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए 21.2.2000 को सार्वजनिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया । अपने विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें । पार्टियों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर ले तथा उनके प्रत्युत्तर यदि कोई हों ।

(vi) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्षों के अगोपनीय अंशोंवाली फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी ।

(vii) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए तर्क, जिन्हें अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, उन्हें संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । परन्तु हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है ।

(viii) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार का ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के लिए खुलासा किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विविधत विचार किया गया है ।

(ix) इस मामले में मानी गई जांच की अवधि 1.4.98 से 31.3.99 है ।

**ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच**

2. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों में और प्रकटन विवरण-पत्र में भी चर्चा की गई है । जिन विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और प्रकटन विवरण-पत्र में पहले विचार नहीं किया गया है और जो मुद्दे अब प्रकटन विवरण के जबाब में उठाए गए हैं, उन पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक वे नियमों के अनुसार संगत हैं और जहां तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं । हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए

तर्कों की जांच की गई है और जहां कहीं भी उचित समझा गया है, नीचे दिए संगत पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है ।

ग. स्थिति

3. प्राधिकारी यह भी करते हैं कि याचिकाकर्ता को स्थिति के बारे में हितबद्ध पक्षों द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है ।

घ. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तुएं

4. विचाराधीन उत्पाद एक साइकलिक एल्कोहल तथा उसके हैलोजिनेटिड सल्फेनेटिड, नाइट्रोट्रोसेटिड अथवा नाईट्रोसेटिड अपसारण हैं जिन्हें वाणिज्यिक तथा तकनीकी भाषा औक्सो एल्कोहल कहते हैं और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं 0 2905 के अंतर्गत उल्लिखित है । प्राधिकारी दिनांक 3.12.1999 के प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 56 तथा 18 में अपनी टिप्पणी का पुनः अवलोकन करते हैं जिनमें इस आधार पर जांच को औक्सो एल्कोहल की केवल कुछ किस्मों अर्थात् सामान्य बुटानोल, आइसो बुटानोल, आईसो डिकानोल, आईसो ओकटानोल, 2-ईथाइल हैक्सानोल तथा सामान्य हैक्सानोल तक सीमित करने का निर्णय लिया गया था कि वे केवल ऐसी किस्में हैं जो कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अथवा आयातित अथवा दोनों की जाती रही हैं ।

5. घरेलू उद्योग तथा आयातकों दोनों ने विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के कार्य क्षेत्र तथा परिभाषा के बारे में विवाद उठाया है । घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र तथा शुल्क को औक्सो एल्कोहल की उन सभी किस्मों पर लागू किया जाना चाहिए जिनका भारत में उत्पादन किया गया है अथवा जिनके लिए भारतीय उद्योग के पास उत्पादन करने की क्षमता तथा योग्यता है । उन्होंने तर्क दिया है कि भारत में समान वस्तु की विशेष किस्म के वास्तविक उत्पादन किस्मों कां उत्पादन करने की क्षमता तथा योग्यता होना अधिक महत्वपूर्ण है । इसके अलावा केवल इस आधार पर किसी विशेष किस्म को शुल्क के दायरे से बाहर रखने से कि उक्त किस्म का आयात नहीं किया गया था, घरेलू उद्योग को लगातार क्षति पहुँच सकती है क्योंकि एक बार अन्य किस्मों पर शुल्क की पुष्टि हो जाने के बाद आयातक इस किस्म का आयात करना शुरू कर सकते हैं । दूसरी और आयातकों ने यह अनुरोध किया है कि जांच के क्षेत्र को केवल घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक रूप से उत्पादित औक्सो एल्कोहल की किस्मों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए । उन्होंने कहा है कि घरेलू उद्योग शब्द का आशय केवल उनसे है जो कि वास्तविक उत्पादनकर्ता है । उन्होंने निवेदन किया है कि सामान्य हैक्सानोल का इस्तेमाल डी एच पी के उत्पादन में किया जाता है जबकि 2-ईथाइल हैक्सानोल का उपयोग डी ओ पी के उत्पादन में किया जाता है तथा इसलिए सामान्य हैक्सानोल को 2-ईथाइल हैक्सानोल के प्रतिस्थापी नहीं माना जाना चाहिए । इस आधार पर आयातकों ने सामान्य हैक्सानोल को पाटनरोधी जांच के कार्यक्षेत्र से बाहर रखने का अनुरोध किया है क्योंकि इसका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है ।

6. इन तर्कों की जांच की गयी है और यह नोट किया गया है कि हालांकि सामान्य हैक्सानोल का प्रयोग 2-ईथाइल हैक्सानोल के स्थान पर भले ही नहीं किया जा सकता हो, किन्तु जिन उत्पादों के उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है, वे एक दूसरे के स्थान पर अदल बदल कर उपयोग किए जा सकते हैं और इसलिए एक किस्म को पाटनरोधी जांच से बाहर रखने का अन्यों के उपयोग पर प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त बातों को तथा प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 5 में पहले से दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद अथवा 'समान वस्तुएं' की परिभाषा के कार्यक्षेत्र को सीमित करने अथवा बढ़ाने का कोई कारण नहीं पाते हैं। और प्रारंभिक निष्कर्षों में अपनायी गई परिभाषा को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। अतः प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों में अपनाए गए 'समान वस्तुओं' के कार्यक्षेत्र तथा परिभाषा की पुष्टि करते हैं।

7. **सामान्य भूल्य तथा निर्यात कीमत**

7). वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अधीन, भारत निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन निर्यातकों ने जवाब दिया उनके द्वारा उठाए गए तर्कों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में विचार किया गया है।

8. मै. जाकलेडी अजोलो कैडजिरजाइन एसए (जैक) पोर्टेंडः मै. जैक ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने भारतीय बाजार में ओक्सो एल्कोहल की बहुत कम मात्रा की आपूर्ति की है जो कि उनके कुल निर्यात का 0.7% है और भारतीय उत्पादन का केवल 1.1% है। भारत में उनकी विक्री यूरोपीय संघ की व्यापारिक कम्पनियों द्वारा की गई थी और इन्ही कम्पनियों पर डम्पिंग के लिए विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यूरोपीय संघ की इन कम्पनियों को भारत में उनके ओक्सो एल्कोहल के वास्तविक निर्यातक के रूप में माना जाना चाहिए जिन्हें अपनी निर्यात कीमत स्वयं तय करने का स्वतन्त्र अधिकार है। इसलिए यह कहा गया है कि ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैक को भारत में ओक्सो एल्कोहल के

निर्यात के मामले में पाटन प्रक्रिया के उपयोग के आरोप के दायरे में लाने का कोई आधार नहीं है ।

**प्राधिकारी द्वारा जांचः-** न्यूनतम आयात की मात्रा के उद्देश्य से उत्पाद के कुल आयात की मात्रा के सन्दर्भ में गणना की जाती है और यह देखा गया है कि पोलैंड से भारत में ओक्सो एल्कोहल का आयात न्यूनतम से अधिक हुआ है । पाटनरोधी जांच में विनिर्माण के स्रोत से वस्तुओं की जो मूलता होती है उसे ही निर्यात बिन्दु और पाटन का स्रोत माना जाता है । चूंकि पाटित वस्तुएं मैं जैक, पोलैंड में विनिर्मित हैं; इसलिए सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना देने के लिए उन्हीं से अनुरोध किया गया था, जो उन्होंने प्रस्तुत नहीं की हैं ।

9. मै. एल.जी. कैमिकल्स, दक्षिण कोरिया द्वारा दिए गए तर्क : दिनांक 3.1.2000 के अपने पत्र में किए गए निवेदनों में मै. एल.जी. कैमिकल्स ने कहा है कि उसने जांच अवधि के दौरान भारत को केवल 4129 मी. टन ओक्सो एल्कोहल का निर्यात किया था जो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रारम्भिक जांच परिणाम में कोरिया से निर्यात की बतलाई गई मात्रा से कम है । उन्होंने अपने सामान्य मूल्य के लिए अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने का वचन दिया था ।

**प्राधिकारी द्वारा जाँचः** निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रारंभिक जांच परिणाम में दक्षिण कोरिया से निर्यात की गई कुल मात्रा का उल्लेख किया गया था । कोरिया से मै. एल.जी. कैमिकल्स के अलावा और निर्यातक भी हो सकते हैं क्योंकि डीजीसीआई इंड एस से लिए गए आंकड़ों में व्यौरे देश-वार है न कि निर्यातक-वार । तथापि, एल.जी. से निर्यात की मात्रा, न्यूनतम मात्रा से काफी अधिक है । एल.जी. ने प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद प्रस्तुत किए गए अपने अभ्यावेदन में अपने सामान्य मूल्य के संदर्भ में कोई अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की है । प्रारंभिक जांच परिणाम में निर्यातकों की निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के संबंध में की गई टिप्पणियों का उन्होंने कोई समाधान नहीं किया है ।

10. मै. ओग्जैनो आलिफिन कैमिक जीएमबीएच, जर्मनी द्वारा दिए गए तर्कः प्रारम्भिक जांच परिणाम से पहले अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए दी गई समयावधि की समाप्ति के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्राप्त दिनांक 20.10.1999 के अभ्यावेदनों में उन्होंने कहा है कि उनके उत्पाद का निर्यात भारत में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर किया गया है और वे किसी प्रकार की पाटन नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं । जांच अवधि में कीमतें अनन्य रूप से प्रचलित बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित की गई थीं और भारत को निर्यात किए जा रहे उत्पादों की कीमतें बिना किसी अपवाद के तत्कालीन प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत स्तर की रेंज में थीं । उन्होंने आगे कहा है कि प्रतिपाटन संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.1 में यह व्यवस्था है कि किसी उत्पाद का पाटन करना यानि इसे सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर दूसरे देश को बेचना तब माना जाएगा जब एक देश से दूसरे देश को निर्यात किए गए उत्पाद की निर्यात कीमत सामान्य व्यापार प्रक्रिया में समान उत्पाद की तुलनीय कीमत से कम हो, जब उक्त समान उत्पाद निर्यातक देश में उपभोग के लिए आशायित हो । कम्पनी ने कहा है कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उसके घरेलू बाजार और निर्यात बाजार में बिक्री के बीच कोई महत्वपूर्ण कीमत अन्तर नहीं है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते

हुए वे महसूस करते हैं कि कीमत और लागत ढांचे पर और ब्यौरे तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ओरजैनो ने कहा है कि वे मानते हैं कि उनके बिक्री आंकड़ों के एकमात्र आधार पर भारत में निर्यातित आक्सो एल्कोहल के पाटन का आरोप ने केवल अस्पष्ट है, अपितु इसका पहले ही खंडन भी हो गया है और शुरू की गई जांच को उपर्युक्त आधार पर रोक दिया जाना चाहिए।

**प्राधिकारी द्वारा जांच:-** मै. ओरजैनो, जर्मनी को सम्बोधित पत्राचार में यह कहा गया था कि घरेलू बिक्री कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में केवल तभी लिया जाता है जब ये बिक्रियाँ सामान्य व्यापारिक कारोबार में की गई हों, जिसका अर्थ यह है कि यह प्रमाणित किया जाना है कि ये बिक्रियाँ ऐसी पर्याप्त कीमत पर की गई हैं, जिससे सकल औसत उत्पादन लागत और लाभ की सामान्य दर की वसूली हो सकें। कम्पनी से अनुरोध किया गया था कि उन्हें भेजी गई प्रश्नावली में दिए गए प्रोफार्मा में वे कीमत और बिक्री लागत के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें। उनसे यह भी कहा गया था कि वे घरेलू बिक्री के सौदावार ब्यौरे और समायोजनों के दावे दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करें। तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी परिकलन के लिए मै. आरजैनों द्वारा प्रस्तुत सूचना का उपयोग नहीं कर सका और ऐसी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास करना पड़ा है जो याचिकाकर्ताओं ने उपलब्ध कराई थी।

11. मै. अलजुबेल फर्टिलाइजर कं. (समद) द्वारा दिया गया तर्क: अपने अभ्यावेदन में कम्पनी ने मै. साबिक मार्केटिंग के साथ अपने संबंधों के ब्यौरे दिए हैं। 2-ई एच के आयात के संबंध में यह कही गया है कि समद और मै. साबिक के बीच एक विपणन करार है जिसके तहत साबिक समद को बेचे गए सभी उत्पादों के लिए 'निवल वापसी कीमत' का भुगतान करता है। यह निवल वापसी कीमत उस कीमत के बराबर है जिस कीमत पर तीसरी पार्टी को वास्तव में उत्पाद की बिक्री उसमें से व्यय और बाजार शुल्क घटाने के पश्चात की जाती है। उक्त व्यय में, समुद्री भाड़ा, बीमा, पत्तन प्रभार इत्यादि से जुड़ी लागत शामिल हैं। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए इन समायोजनों के दावे किए गए हैं, जिसकी अनुमति दे दी गई है।

प्रारम्भिक जांच परिणाम के पश्चात् कम्पनी ने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर अभिकलित सामान्य मूल्य पर भरोसा ने किया जाए और उनके द्वारा उत्पादन लागत के संबंध में मुहैया कराई गई सूचना का उपयोग सामान्य मूल्य निकालने के लिए किया जाए। चूंकि साउदी अरब में 2-ई एच की कोई घरेलू बिक्री नहीं है इसलिए सामान्य मूल्य के लिए संगत सूचना उत्पादन लागत है। कम्पनी ने जांच अवधि के दौरान माह-वार उत्पादन लागत के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और यह देखा गया है कि माहवार औसत उत्पादन लागत में काफी अन्तर है, जो कम्पनी के अनुसार कच्चे माल की कीमत में उतास-चढ़ाव के कारण है। कैम्पनी द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि पाटन - मार्जिन का निर्धारण निर्यात के महीने के पूर्ववर्ती महीने की उत्पादन लागत की निर्यात कीमत के साथ तुलना के आधार पर किया जाए क्योंकि बारह महीनों की सकल अवधि के दौरान भारत को केवल 4 निर्यात सौदे सम्पन्न हुए हैं। इसलिए उन्होंने यह अनुरोध किया था कि पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली निर्यात कीमत और औसत उत्पादन लागत की सौदा-दस-सौदा आधार पर

तुलना है । पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-। के पैरा 2(1) के अनुसार आगे यह तर्क दिया गया है कि संगत उत्पादन लागत के साथ बिक्री कीमत की तुलना उचित तुलना के लिए स्वीकृत पद्धति है और जब उस निश्चित सौदे की कथित बिक्री कीमत उत्पादन की लागत से कम हो तभी यह पता लगाने की आवश्यकता है कि जांच अवधि के लिए क्या बिक्री कीमत भारित औसत उत्पादन लागत से कम है या अधिक है । जिससे कि यह मालूम हो सके कि क्या उक्त सौदे सामान्य व्यापार कारोबार के तहत हुए हैं ।

कम्पनी के अनुरोधों के जवाब में उनको किए गए पत्राचार में कम्पनी से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्यात के महीने के पूर्ववर्ती महीने की औसत उत्पादन लागत का उपयोग करने के लिए उनके अनुरोध का आधार क्या है । उन्हें यह भी बतला दिया गया था कि उनके द्वारा उद्भूत उक्त नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 2(1) का संबंध उस स्थिति से है जहाँ सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री सौदों का उपयोग किया जाना हो । उन्हें यह भी बताया गया था कि अगर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माहवार औसत उत्पादन लागत का उपयोग करने का निर्णय लिया जाए, तब भी उस महीने के लिए उत्पादन लागत का उपयोग करना अधिक उपयुक्त होगा जिस महीने में तुलना किया जाने वाले निर्यात सौदों के आदेश के लिए मांग-पत्र भेजा गया हो ।

अपने परवर्ती पत्राचारों में कम्पनी के वकीलों ने यह स्वीकार किया था कि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 का पैरा 2(1) घरेलू बिक्री सौदे के मूल्यांकन से संबंधित है न कि उत्पादन लागत से । लेकिन उन्होंने इस पैरा का उल्लेख इसमें मान्य सिद्धान्त को प्रदर्शित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में किया था । यह भी कहा गया था कि सिद्धान्त यह है कि बिक्री के समय कोई विशेष सौदा या तो उत्पादन लागत से अधिक कीमत पर किया जा सकता है अथवा जांच अवधि के लिए भारित औसत लागत से अधिक कीमत पर किया जा सकता है और दोनों स्थितियों में सौदे को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा । यह भी स्वीकार किया गया था कि चूँकि जांच अवधि में उन्हें नुकसान हुआ था और उनकी घरेलू बिक्री नहीं हुई इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण उनके उत्पादन लागत जमा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च जमा लाभ के संदर्भ में किया जाय । तथापि, जांच अवधि के दौरान प्रोपीलीन जो एक प्रमुख कच्ची सामग्री है की कीमतों में बहुत अधिक उत्तार-चढ़ाव था, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की मासिक औसत लागत में काफी भिन्नता आई है । इसके आलोक में ही उन्होंने निर्यात सौदों, जो केवल 4 ही सौदे थे, की तुलना मासिक औसत उत्पादन लागत के साथ करने का अनुरोध किया था । जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है कि किस महीने की उत्पादन लागत का प्रयोग किया जाए उसके बारे में पूर्ववर्ती महीने की उत्पादन लागत का प्रयोग करने का अनुरोध इस आधार पर किया था कि माल का विनिर्माण आमतौर पर पूर्ववर्ती महीने में किया जाता है और इसमें निर्यात किए जा रहे माल की उत्पादन लागत विधिवत् रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए ।

**प्राधिकारी द्वारा जांच:** मैसर्स समद द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों की जांच करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकांश तर्क प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिए हैं । खर्चों के रूप में किए गए समायोजन दावे जैसे समुद्री भाड़ा, बीमा, बैट बैक प्राइस निकालने के लिए पत्तन भार और साबिक को देय विपणन शुल्क की अनुमति दावानुसार दी गई है । निर्यातक द्वारा दिए गए तर्क एवं अनुरोध के अनुसार डम्पिंग मार्जिन निकालने के लिए सौदा दर सौदा दृष्टिकोण अपनाते हुए औसत मासिक उत्पादन लागत का प्रयोग करने की भी अनुमति दी गई है । तथापि, यह तर्क की किसी निर्यात सौदे के लिए सामान्य मूल्य के रूप में पूर्ववर्ती महीने की औसत उत्पादन-लागत का प्रयोग करने की बात स्वीकार्य नहीं है । उस महीने की औसत उत्पादन लागत का प्रयोग करना अधिक उचित है जिस महीने में निर्यात आर्डर का मांग पत्र भेजा गया हो क्योंकि यह संभावना होती है कि उस विशेष महीने की उत्पादन लागत के आधार पर ही बिक्री के लिए एक निश्चित कीमत उद्धृत की जाएगी । यद्यपि कम्पनी कुछ अपेक्षाओं के आधार पर कार्य करेगी लेकिन जैसा कि स्वयं निर्यातकों ने स्वीकार किया है, प्रोपीलीन की लागत में अत्यधिक उत्तार-चढ़ाव रहा है और इसका हिस्सा विभिन्न उत्पादन लागत का 80 % बनता है । इसलिए उत्पादन के समय निर्यातक के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि निर्यात के समय उसकी संभावित लागत क्या होगी । इसलिए तुलना करने और पार्टन मार्जिन निकालने के प्रयोजनार्थ उस महीने की औसत उत्पादन लागत को लेना सर्वोत्तम रहता है जिस महीने में विशेष निर्यात सौदे की मांग की जाती है । तदनुसार डम्पिंग मार्जिन की गणना की गई है । जैसा कि सौदावार दृष्टिकोण अपनाने की आम परिपाटी है, डम्पिंग मार्जिन निकालने के प्रयोजन से केवल पाटित सौदों को ही हिसाब में लिया जाता है ।

प्रकटीकरण विवरण-पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया गयाथा कि प्राधिकारी डम्पिंग मार्जिन निकालने के लिए ऊपर स्पष्ट की गई विधि का प्रयोग करना चाहते हैं। प्रकटीकरण विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में निर्यातकों के वकीलों ने आगे अनुरोध किया है कि कीमतें उत्पादन लागत के आधार पर नहीं हैं बल्कि प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर ही हैं और इन मांग-पत्रों में जो कीमतें अंकित की गई हैं वे क्रेता द्वारा इंगित पोतलदान के समय पर निर्भर रहते हुए सहमत कीमतें हैं।

यदि निर्यातक के तर्कों को स्वीकार कर भी लिया जाता तो सामान्य मूल्य के रूप में महीनावार उत्पादन लागत का कोई आधार नहीं है। इससे सामान्य मूल्य के रूप में महीने की औसत उत्पादन लागत का प्रयोग करने के निर्यातक के अनुरोध का खंडन होता है इसलिए प्राधिकारी को निर्यातक का तर्क स्वीकार्य नहीं है और ऊपर की गई गणना को डम्पिंग मार्जिन निकालने हेतु ध्यान में रखा गया है।

12. घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्क: डम्पिंग मार्जिन के बारे में अपने अनुरोध में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निर्यात कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत डी जी सी आई एस की सूचना में कुछ असाधारण सौदे निहित हैं जिनमें असामान्य तौर पर ऊंची निर्यात कीमतें बतलायी गई हैं। उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई में किए गए अनुरोधों और उसके बाद प्रस्तुत लिखित अनुरोधों में इनमें से कुछ सौदों की सूची तैयार की है।

प्राधिकारी द्वारा जांच: इसकी जांच की गई है और यह देखा गया है कि इनमें से कुछ सौदे द्रम पैकिंग में बिक्री से संबंधित हो सकते हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि केवल उन सौदों की अनदेखी की जाय जिनके लिए प्राधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। तदनुसार, डम्पिंग मार्जिन की पुनः गणना की गई है।

13. अन्य देश: जो सूचना निर्यातकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी वह शेष देशों अर्थात् ईरान, पोलैण्ड, इण्डोनेशिया, रूस और यूरोपीय संघ के किसी भी निर्यातक से प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि इन देशों के निर्यातकों को अथवा अन्य हितबद्ध पक्षों ने सामान्य मूल्य के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए प्राधिकारी ने इन देशों का सामान्य मूल्य निकालने के लिए याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया है। ऐसे मामलों में 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धरा 9 क(1) (ग) और पाटनरोधी नियमों के नियम 6(8) जो प्राधिकारी को उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पूर्व देश की उत्पादन लागत निकालने के लिए प्राधिकृत करता है, के अनुसार उचित समायोजन के साथ भारतीय उद्योग के लागत आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य निकाला गया है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि उत्पादन में आई लागत निकालने के लिए कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है डी जी सी आई एस से उपलब्ध सूचना और आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का प्रयोग आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए किया गया है।

14. नए निर्यातक: कुछेक निर्यातकों/विनिर्माताओं ने दावा किया है कि उन्होंने जांच अधिक के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किया है। ऐसी परिपाटी रही है कि 'नए निर्यातक भारत को निर्यात करते हैं तो उपरोक्त पाटनरोधी नियमों के नियम 22 के तहत एक नए निर्यातक के रूप में वे समीक्षा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

च. पाटन - सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना त्वचा पाटन मार्जिन

15. उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पादों के लिए संबद्ध देशों के मामले में प्रतिशत के रूप में (समायोजन करने के पश्चात् निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में) निम्नानुसार डम्पिंग मार्जिन निकाला है:-

### डम्पिंग मार्जिन

देश	एन बी ए	1आई बी ए	2 ई एच ए
पोलैण्ड	69.82		56.65
दक्षिण कोरिया	106.73	140.19	109.05
रूस	102.73	111.94	
ईरान	107.85	130.1	
यू एस ए	50.67	77.85	69.79
ई यू	110.09	130.77	45.5
इंडोनेशिया		164.03	104.23
सऊदी अरब			13.08

मैसर्स एल जी कैमिकल्स के लिए यथानिर्धारित डम्पिंग मार्जिन का प्रयोग समूचे दक्षिण कोरिया के लिए किया गया है। इसी प्रकार मैसर्स साऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एस ए बी आई सी) की एक सहायक कंपनी मैसर्स अल जुबैल फर्टिलाइजर्स कम्पनी (एस ए एम ए डी) के लिए निर्धारित डम्पिंग मार्जिन साऊदी अरब से भारत को होने वाले सभी आयातों पर लागू होता है। जहां डी जी सी आई एस के आंकड़े किसी विशेष संबद्ध देश से भारत को ओक्सो अल्कोहल की किसी खास किस्म का कोई आयात नहीं दर्शाते हैं वहां विशेष संबद्ध देश से ओक्सो अल्कोहल की उक्त विशेष किस्म के डम्पिंग मार्जिन से संबंधित खाली छोड़ दिया गया है।

#### ८. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

१६. जैसे कि प्रारम्भिक निष्कर्ष के पैराग्राफ 11 में चर्चा की गई है, पाटनरोधी नियमों के नियम 11 में उल्लिखित अनुबंध II की अपेक्षाओं के अनुसार क्षति संबंधी मानदंडों पर विचार किया गया है, जिसमें क्षति के विश्लेषण के लिए विचार किए जाने वाले मानदंडों का उल्लेख किया गया है। इनमें दिए गए कारणों के मद्देनजर, संबद्ध देशों से हुए आयातों के लिए क्षति का निर्धारण संचयी रूप से किया गया है क्योंकि ये आयात भारतीय बाजार के घरेलू उद्योग के साथ सीधे मुकाबला करते थे और संचयी गणना के लिए अन्य शर्तों को भी पूरा करते थे। संबद्ध देशों से होने वाले आयातों के रुख, उनका बाजार हिस्सा, कुल मांग में हिस्सा, निर्यात कीमत का रुख तथा विभिन्न अन्य मानदंडों जैसे कारकों के आधार पर प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्ष के समय क्षति संबंधी कुछ निष्कर्ष निकाले थे, जो नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

- (क) संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ;
- (ख) संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि भारत में ऑक्सो अलकोहल के कुल आयात के संदर्भ में हुई है ;
- (ग) भारत में ऑक्सो अलकोहल की मांग के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि घरेलू उद्योग का बाज़ार हिस्सा घट गया है।
- (घ) घरेलू उद्योग के ऑक्सो अलकोहल के उत्पादन में कमी आई है ;
- (ङ.) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कमी आई है ;
- (च) वास्तविक मात्रा एवं मूल्य के रूप में घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है ;
- (छ) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में तीव्र गिरावट आई है ;
- (ज) आयात द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें महत्वपूर्ण रूप से कम हो रही हैं ;
- (झ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता गंभीर रूप से कम हुई है।

प्राधिकारी ने इन आकलनों के आधार पर यह निर्णय दिया था कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि जांच-अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयात की मात्रा में वृद्धि होने से याचिकार्कर्ताओं के बाजार हिस्से में कमी आई है तथा घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद को उचित बिक्री कीमत से कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसे हानि हुई है। इन आकलनों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया था कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से आयात के कारण हुई है। तथापि, प्रारम्भिक जांच के बाद हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए निवेदनों में क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में तर्क दिए गए थे जिन पर नीचे चर्चा की गई है।

17. भारतीय प्लास्टिसाइजर्स विनिर्माता संघ तथा यूरोपीय आयोग (ईसी) द्वारा दिए गए तर्क

यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों के आयातों की कुल मात्रा एवं बाजार हिस्से में वृद्धि का कारण घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में घरेलू उत्पादकों की असमर्थता है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में आई कमी बिलकुल ही पाटन संबंधी कारणों से नहीं थी। आंत्र पेट्रोकेमिकल के मामले में यह तर्क दिया गया है कि यह प्लांट एचपीसीएल शोधशाला से प्रोपीलीन की आपूर्ति नहीं होने के कारण दिनांक 21.5.98 तक बंद था। मै0 इंदू निस्सान ऑक्सो कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में यह तर्क दिया गया है कि वित्तीय समस्याओं के कारण उन्होंने पानी तथा बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया और उनके पानी तथा बिजली के कनेक्शन महीनों से कटे हुए थे जिसके कारण वे उत्पादन नहीं कर सके। एन ओ सी आई एल के मामले में यह कहा गया है कि पुराना संयंत्र होने के कारण इसमें बार-बार खराबी आती रही। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उत्पादक स्थानीय उद्योग के लिए ऑक्सो अलकोहल की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से होने वाले आयात की मात्रा में वृद्धि हुई ताकि घरेलू मांग एवं पूर्ति के बीच के अंतर को भरा जा सके। यह भी तर्क दिया गया है कि ऑक्सो अलकोहल की घरेलू क्षमता बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना में काफी कम है इसलिए यह अलाभकारी है और प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में असमर्थ है।

इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है कि वास्तविक क्षति तथा कारणात्मक संबंध प्रमाणित नहीं होता है और तदनुसार जांच समाप्त कर दी जाए। भारत से आए यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल ने भी अपने निवेदन में यह कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या भारतीय पाटनरोधी प्राधिकारियों ने कथित पाटन के अलावा उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारणों की भी जांच की है अथवा नहीं।

प्राधिकारी द्वारा जांच:

प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण करते समय क्षति से संबंधित सभी संकेतकों को ध्यान में रखा है। इसमें सभी संगत तथ्य अर्थात् पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में कीमतों पर इनका प्रभाव और घरेलू उत्पादकों, उत्पादन, क्षमता उपयोगिता, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली इत्यादि पर बाद में पड़ने वाले इसके प्रभाव, शामिल हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग में शामिल कंपनियों द्वारा दी गई सूचनाओं की जांच तथा विस्तृत विश्लेषण करने के पश्चात संबद्ध वस्तुओं के लिए एक क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया था।

ज. अन्तिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त बातों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं :

(क) पोलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सउदी अरब, रूस, ईरान, अमरीका तथा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आक्सो अलकोहल (केवल नार्मल बूटानोल, आईसो बूटानोल, आइसो डेकानोल, आइसो ऑक्टानोल 2-इथाइल हेक्सानोल तथा नार्मल हेक्सानोल) का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ।

(ख) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

(ग) संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण संचयी रूप से क्षति हुई है ।

19. प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि पाटन के मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम ऐसा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाए जिसे अगर लागू किया जाए तो उससे घरेलू उद्योग की क्षति दूर हो जाएगी । क्षति के निर्धारण के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया जाता है कि आयात के पंहुच मूल्य की तुलना जांच-अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनी की अक्षतिकारक बिक्री कीमत से की जाए ।

20. प्राधिकारी संबद्ध देशों/क्षेत्रों के संबंध में संबद्ध वस्तुओं के आयात पर नीचे सारणी में उल्लिखित राशियों के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं:-

### सिफारिश किए गए शुल्क की राशि

(अमरीकी डालर प्रति मीट्रो टन)

देश	नार्मल व्यूटानॉल	आईसो व्यूटानॉल	2-इथाईल हेक्सानोल एवं अन्य ऑक्सो अलकोहल
पोलैण्ड	44	165	165
दक्षिण कोरिया	115	187	252
रूस	67	97	97
ईरान	79	136	136
अमरीका	58	मूल्य	87
यूरोपीय संघ	145	204	121
इंडोनेशिया	197	194	197
सउदी अरब	47	47	47

‘ 2-इथाईल हेक्सानोल एवं अन्य ऑक्सो अलकोहल’ शीर्षक के तहत अंतिम कालम में उल्लिखित शुल्क की राशि आईसो डेकानोल, आईसो ऑक्टोनोल तथा नार्मल हेक्सानोल के लिए भी लागू होती है। जहां कहीं जांचाधीन ऑक्सो अलकोहल के विशिष्ट रूप का आयात नहीं हो रहा है, वहां संबद्ध देश से निर्यात हो रहे ऑक्सो अलकोहल के अन्य रूपों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ऊपर दी गई सारणी में शुल्क की अवशिष्ट दर की सिफारिश की गई है।

21. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पंहुच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा जिसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3,3 क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्क शामिल होंगे।

22. उपरोक्त बातों के अधीन, प्राधिकारी दिनांक 3.12.99 के प्रारम्भिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

23. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी।

रति विनय ज्ञा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2000

**FINAL FINDINGS**

**Subject : Anti dumping investigation concerning imports of Oxo alcohols from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and the European Union : Final Findings**

**No. 15/1/99-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

**A. Procedure**

1. The procedure described below has been followed:

(i) Based on the petition filed by the Oxo alcohol Industries Association comprising of, Messrs. Indo Nissan Oxo Chemical Industries Limited, Mumbai, National Organic Chemical Industries Limited, Mumbai and Andhra Petro Chemicals Limited, Hyderabad and in accordance with Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, investigation against imports into India of Oxo alcohols from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and the EU

(hereinafter referred to as subject countries/territory) were initiated vide notification No. 15/1/99-DGAD dated 29.7.99.

- (ii) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide notification dated 3.12.99 on anti-dumping investigation concerning imports of Oxo alcohols from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and the European Union and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- (iii) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days from the date of its publication;
- (iv) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the embassies/delegations of subject countries/territory in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (ii) and (iii) above.
- (v) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 21.2.2000. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

- (vi) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;
- (vii) Argument raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in these findings;
- (viii) In accordance with Rule 16 of the Rules *supra*, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- (ix) The period of investigation (POI) considered is 1.4.98 to 31.3.99;

**B. Views of Petitioners, Exporters, Importers and Other Interested Parties and Examination by Authority**

2. The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

### C. Standing

3. The Authority notes that there is no argument raised by interested parties on the standing of the petitioners.

### D. Product Under Consideration and Like Articles

4. The product under consideration is acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives, known as oxo alcohols in the commercial and technical parlance and defined under customs sub-heading No. 2905 of the Customs Tariff Act. The Authority recalls its observations in paras 5, 6 and 18 of the Preliminary Findings dated 3.12.1999 wherein it was decided to restrict the investigation only to some forms of Oxo alcohols viz., Normal Butanol, Iso Butanol, Iso Decanol, Iso Octanol, 2-Ethyl Hexanol & Normal Hexanol on the ground that these are the only forms which are either being produced by the domestic industry or being imported or both during the investigation period.

5. The domestic industry as well as importers have raised arguments on the issue of scope and definition of product under consideration and Like Article. The domestic industry has submitted that the scope of the present investigation and duties should extend to all those types of oxo alcohols which have been produced in India or for which the Indian industry has capacity and capability to produce. They have argued that the fact of actual production of the particular form of Like Article in India is of little consequence and the issue of capacity and capability to produce particular forms is more important. Also exclusion of a particular form from the scope of duty merely because that type was not imported may lead to continued injury to the domestic industry as the importers may start importing this type once duties are

confirmed on other types. On the other hand the importers have submitted that the scope of investigation should be restricted only to the forms of oxo alcohol actually being produced by the domestic industry. They have stated that the term domestic industry refers only to those who are actual producers. They have submitted that Normal Hexanol is used to produce DHP whereas 2-Ethyl Hexanol is used to produce DOP and hence Normal Hexanol should not be taken as a substitute for 2-Ethyl Hexanol. On the basis of this the importers have requested to drop Normal Hexanol from the scope of anti dumping investigation as it is not being produced by the domestic industry.

6. These arguments have been examined and it is noted that though normal Hexanol may not be a substitute for 2-Ethyl Hexanol, the products these are used to manufacture substitute each other and hence exclusion of one from anti dumping duty investigation will have an impact on the usage of others. In view of above and the arguments already given in para 5 of the Preliminary Findings, the Authority does not find any reason to restrict or expand the scope of definition of product under consideration or that of 'Like Article' and has decided to continue with the definition adopted in Preliminary Findings. The Authority therefore confirms the scope and definition of 'Like Articles' adopted in Preliminary Findings.

#### **E. Normal Value and Export Price**

7. The Authority provided opportunity to the known exporters to furnish information in accordance with Section 9A (1) (e) of the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995, cited above. The argument raised by the exporters who responded are discussed in the following paragraphs.

8. **Argument raised by M/s. Zaklady Azolowe Kedzierzyn SA ( ZAK) Poland:** M/s. ZAK, in their submission have stated that they have supplied to the Indian market very small quantities of oxo alcohols which is 0.7% of their total export and only 1.1% of Indian production. Their sale to India was made by trading companies from EU and it is these companies that should be considered for dumping. It is therefore, argued that these EU companies should be treated as real exporter of their oxo alcohols to India with their independent right to create their own export price. It has, therefore, been submitted that taking the above mentioned facts into consideration, there is no basis to bring ZAK into the charge of using the dumping methods in case of export of oxo alcohols into India.

**Examination of by the Authority:** For the purposes of deminimus import volume, the calculations are done with reference to total import volume of the product and it is seen that imports of oxo alcohols into India originating from Poland are more than deminimus. In anti dumping investigation it is the origin of the goods from the source of manufacturer that is considered as the point of export and source of dumping. Since goods dumped have been manufactured at M/s. ZAK, Poland, the information regarding the normal value was requested from them which they have not submitted.

9. **Arguments raised by M/s. LG Chemicals, South Korea:** In their submissions M/s. LG Chemicals vide their letter of 3.1.2000 have stated that they exported only 4129 MTS of oxo alcohol to India during the period of investigation which is less than the amount stated to have been exported from Korea as mentioned in the preliminary finding issued by the Designated Authority. They promised to submit additional information for their normal value.

**Examination by Authority:** In the preliminary findings issued by the Designated Authority it was the total volume of export from South Korea which was mentioned. There might have been exporters other than M/s. LG Chemicals from Korea as the export data from DGCIS provides data country-wise and not exporter-wise. However, even the volume of exports from LG is substantial enough to pass the *deminimus* test. LG have not provided any additional information regarding their normal value in their submissions made subsequent to the preliminary findings. The observations regarding their export price and normal value in the preliminary findings have not been addressed by the exporters. The Authority therefore confirms the methodology adopted for computation of normal value and export price in case of Korea RP as detailed in para 9 of the Preliminary Finding.

10. **Arguments raised by M/s. OXENO Olefinchemic GmbH, Germany:** In their submissions dated 20.10.99, received by the Designated Authority after the expiry of the time period allowed for making submissions before the preliminary findings, they have stated that their products are exported to India at competitive prices and they do not pursue dumping policy of any kind. The prices in the period under investigation were determined exclusively by the prevailing market conditions and the prices of products being exported to India fall within the international price range prevailing at that time, without exception. They have further stated that Art. 2.1 of WTO Agreement on Anti Agreement stipulates that a product has to be considered as being dumped i.e, introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade for the like-product when destined for consumption in the exporting country. The company has submitted that from the above it is evident that no significant difference in price exist between sales on their domestic market and the export markets. In view

of the above they feel that there is no need to draw up further details on price and cost structures. M/s. Oxeno have submitted that they believe that on the sole basis of their sales figures, the charge of dumping oxo-alcohol exports in India is not only non-obvious, but has already been disproved and the initiated investigation be suspended on the above grounds.

**Examination by the Authority:** In the communication addressed to M/s. Oxeno, Germany, it was stated that the domestic sale price is taken as normal value only if these sales are in the ordinary course of trade which implies that it has to be proved that these sales are at a price sufficient to recover total average cost of production and normal rate of profit. The company was requested to furnish the information regarding price and cost of sales in the format given in the questionnaire which was sent to them. They were also asked to give details of domestic sales transaction-wise alongwith the adjustment claimed supported by documentary evidence. However, no such information has been received by the Designated Authority. In view of the above, the Authority cannot use the information furnished by M/s. Oxeno for the purposes of calculation and has to rely on the best information available which has been provided by the petitioners.

**11. Arguments made by M/s. Al Jubail Fertilizer Company (SAMAD):** In their submissions, the company has given details of their relation with M/s. Sabic Marketing Limited. Regarding the import of 2-EH, it is stated that there is a marketing agreement between SAMAD and M/s. SABIK in terms of which SABIK pays SAMAD "netback price" for all the products sold. This Netback price is equal to the price at which the product is actually sold to the third party, less expenses and marketing fee. The expenses are costs associated with ocean freight, insurance, port

charges etc. These adjustments have been claimed for arriving at the Net Export Price which have been allowed.

Subsequent to preliminary finding the company requested that the normal value calculated on the basis of the information submitted by petitioner should not be relied upon and instead the information provided on the cost of production by them should be used for arriving at the normal value. As there is no domestic sale of 2EH in Saudi Arabia the relevant information for normal value is the cost of production. The company has provided data on month wise cost of production during the period of investigation and it is observed that there is significant variation in the average cost of production month-wise which (according to company) is because of fluctuating cost of the raw material. It was submitted by the company that dumping margin should be determined based on the comparison of the cost of production of the month preceding the month of export with the export price as there are only 4 export transactions to India during the entire period of twelve months. It was therefore submitted by them that the comparison of the export price and average cost of production on transaction to transaction basis is the most appropriate method of determining dumping margin. As per para 2(ii) of Annexure I of the Anti Dumping Rules, it is further contended that the comparison of selling price with the corresponding cost of production is the permitted method of fair comparison and only when the said selling prices are below the cost of production of that particular transaction, there is a need to find out whether the selling prices were above or below weighted average cost of production for the period of investigation to consider these transactions having been in the ordinary course of trade.

In the reference made to the company in reply to their submissions, the company was asked to clarify the basis of their request for using the average cost of

production of the month preceding the month of export for arriving at the normal value. It was also pointed out to them that para 2(ii) of Annexure I of the said Rules, quoted by them relates to situation where domestic sale transactions are to be used for arriving at the normal value. It was also pointed out to them that even if the Designated Authority decides to use month wise average cost of production for arriving at the normal value, it will be more appropriate to use the cost of production for the month in which the order for export transaction being compared was indented.

In their subsequent communications, it was admitted by the advocates for the company that para 2(ii) of Annexure I of the Anti Dumping Rules relates to evaluation of domestic sale transaction and not to cost of production but they had referred to the said para as an illustration to show the principle recognised therein. It was further stated that the principle is that a particular transaction could either be above the cost of production at the time of sale or it could be above the weighted average cost for the period of investigation and in both situations the transaction is to be treated as in the ordinary course of trade. It was also admitted that as they had incurred losses for the period of investigation and they do not have domestic sales it becomes necessary to determine the normal value with reference to their cost of production plus selling, general and administrative expenses plus profit. However, there have been violent fluctuations in the prices of propylene, a major raw material, during the period of investigation which has resulted in significant variations in the monthly average cost of production. It was in this light that they had requested to compare the export transaction which are only 4 with the monthly average cost of production. Regarding the question of which month's cost of production to be used, their submission was to use the preceding month's cost of production on the ground that the goods are normally manufactured in the preceding month and that should be duly reflecting the cost of production of the goods being exported.

**Examination by the Authority:** After having gone through the detailed submissions made by M/s. SAMAD, most of the arguments presented by them have been accepted by the Authority. Adjustments claimed as expenses such as ocean freight, insurance, port charges for arriving at 'net back price' and marketing fee payable to SABIK is allowed as claimed. 'Also using transaction by transaction approach and use of average monthly cost of production for arriving at a dumping margin as argued and requested by the exporter is also allowed. However, the logic that previous month's average cost of production should be used as normal value for a particular export transaction is not acceptable. It is more appropriate to use the average cost of production in the month in which the export order was indented as the cost of production of that particular month is likely to be the basis for quoting a particular price for sale. Though the company would work on some expectations but as admitted by the exporters themselves there have been violent fluctuations in the cost of propylene which constitutes 80% of the variable cost of production. It is, therefore, not possible for the exporter to anticipate the likely cost at the time of production for export. So it is most appropriate to take the average cost of production for the month in which particular export transaction is indented for the purpose of comparison and arriving at dumping margin. The calculations for dumping margin have been done accordingly.

It was stated in the Disclosure Statement that the Authority intends to use the methodology explained above for arriving at the dumping margin. In response to the disclosure statement, the advocates for the exporter have made further submission that the prices are not based on the cost of production but only on the prevailing international prices and that the prices indicated in these indents are agreed upon depending on the timing of the shipments indicated by the purchaser.

If the arguments of the exporter was to be accepted then the use of month-wise cost of production as normal value has no basis. This contradicts the request of the exporter for using average cost of production of month as normal value. Hence the argument of the exporter is not accepted by the Authority and the calculation as done above are taken into account for arriving at the dumping margin. However, there was a calculation error in dumping margin given in Disclosure Statement which has been since corrected.

**12. Argument by the domestic industry:** In their submissions regarding dumping margin, the domestic industry has contended that DGCIS information used by the Designated Authority for arriving at the export price contains some abnormal transactions suggesting unusually high export prices. They have listed some of these transactions in their submissions made in the public hearing and the written submissions made thereafter.

**Examination by Authority:** This has been examined and it is noticed that some of these transactions may refer to sale in drum packing. It is, therefore, decided to ignore only two of those transactions for which evidence has been furnished to the Designated Authority. The dumping margin has been recalculated accordingly.

**13. Other Countries :** The information as required to be submitted in the prescribed format by the exporters has not been received from any exporter from the rest of subject countries i.e. Iran, Poland, Indonesia, Russia, USA and the European Union. As no information on normal value in these countries has been furnished by the exporters or other interested parties, the Authority has, therefore, considered the information provided by the petitioners for the purpose of arriving at normal value in

these countries. The normal value in such cases has been constructed on the basis of cost data of the Indian industry with appropriate adjustments, in accordance with Rule 6(8) of Anti Dumping Rules and Section 9A(1)© of Custom Tariff Act, 1975 as amended in 1995 which authorise the Authority to work out cost of production in the country of origin on the basis of the facts available with it. Here it may be stated that in arriving at constructed cost of production, international prices of raw materials with adjustments, wherever applicable, are used. Regarding the export price the information available from DGCIS as well as that furnished by the importers has been used for arriving at the export price at ex-factory level after making necessary adjustments.

14. **New exporters :** Some of the exporters/manufacturers have claimed that they have not exported to India during the period of investigations. It has been the practice to allow these exporters to apply for review as new exporter under Rule 22 of Anti-Dumping Rules mentioned above as and when they export to India.

#### **F. Dumping - Comparison of Normal Value and Export Price and Dumping Margins**

15. On the basis of the best information available, the Authority has arrived at the dumping margins in percentage terms (as % of export price after adjustments) in the case of subject countries for products under consideration as follows:

### Dumping Margins

Country	NBA	1BA	2EHA
Poland	69.82		56.65
South Korea	106.73	140.19	109.05
Russia	102.73	111.94	
Iran	107.85	130.1	
USA	50.67	77.85	69.79
EU	110.09	130.77	45.5
Indonesia		164.03	104.23
Saudi Arabia			13.08

Dumping margins as determined for M/s. LG Chemicals have been used for South Korea as a whole. Also dumping margins for M/s. Al Jubail Fertilizers Company (SAMAD), a subsidiary of M/s. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) are applicable to all the imports from Saudi Arabia to India. Wherever the DGCIS data show no import of a particular form of oxo alcohol from a particular subject country to India, the box relating to dumping margin for that particular form of oxo alcohols from the particular subject country has been left blank.

### **G. Injury and Causal Link**

16. As already discussed in paragraph 11 of the preliminary finding, the injury parameters have been considered as per the requirement of Annexure II to the Anti Dumping Rules referred to in Rule 11 wherein the parameters to be considered for injury analysis have been outlined. In view of the reasons given therein, the injury determination has been done cumulatively for the imports from the subject countries

as these imports were directly competing with the domestic industry in the Indian market and also satisfying other conditions required for cumulation. On the basis of the factors such as trend in the imports from the subject countries, their market share, the share of total demand, trend in the export price and various other parameters, the Authority had arrived at certain conclusions at the time of Preliminary finding on injury which are reproduced below:-

- (a) Imports from the subject countries have increased significantly in absolute terms;
- (b) Imports from the subject countries have increased in relation to total imports of Oxo Alcohols in India;
- (c) Imports from the subject countries have increased in relation to demand of Oxo Alcohols in India. As a direct consequence, the market share of the domestic industry has declined;
- (d) Production of Oxo Alcohols of the domestic industry has declined;
- (e) Capacity utilization of the domestic industry has declined;
- (f) Sales in absolute volume & value of the domestic industry have declined;
- (g) Selling prices of the domestic industry have declined steeply;
- (h) Imports are significantly undercutting the selling prices of the domestic industry;
- (i) The profitability of the domestic industry has been severely eroded.

The Authority had concluded on the basis of these assessments that the domestic industry had suffered material injury. It was further stated that the increase in the quantum of imports from subject countries has resulted in decline in the market share of the petitioners and also forced the domestic industry to sell their product below the fair selling price resulting into losses during the period of investigation. On the basis

of these assessments, it was established that the material injury to the domestic industry has been caused by the imports from the subject countries. However, in the submissions made subsequent to the preliminary investigation, arguments regarding the injury and causal link have been received from interested parties which are discussed below.

**17. Arguments by Indian Plasticisers Manufacturers Association, and Delegation of EC:** It has been argued that increase in total quantum and market share of imports from the subject countries was because of the inability of the domestic producers to meet the domestic requirement. The short fall in the production by the domestic industry was because of reasons not related to dumping at all. In the case of Andhra Petrochemical, it is argued that the plant was closed till 21.5.98 because of non supply of propylene from HPCL refinery. In the case of M/s. Indu Nissan Oxo Chemical Industries Limited, it is argued that due to financial problems they did not pay their water and electricity bills and their water and electric connection were cut for months because of which they could not carry on production. In the case of NOCIL it is stated that it being an old plant there were frequent breakdowns. It is therefore, argued that domestic producers were unable to supply required quantities of Oxo alcohols to the local industry which led to increase in the volume of imports from subject countries for meeting the gap between the domestic demand and supply. It is also argued that the domestic capacities of oxo alcohols are very small when compared with multinational corporations and therefore uneconomic and unable to face competition.

It has thus been argued that the injury suffered by the domestic industry is on account of reasons not related to dumping and the Designated Authority is requested to hold that the material injury and causal link have not been established and accordingly

terminate their investigation. In their submissions, the Delegation of European Commission in India have also stated that it is not clear whether the Indian Anti Dumping Authorities have also examined causes other than the alleged dumping which might have caused injury to the industry.

**Examination by the Authority:** The Authority has taken into account all indices regarding injury while doing the injury determination and causal link. This involves all relevant facts viz., volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market and its subsequent effect on domestic producers, production, capacity utilisation, profitability, net sales realisation etc. The Authority also determined a non-injurious price for the subject goods after a detailed analysis and scrutiny of information provided by the companies forming domestic industry. The actual cost of production of the subject goods for the domestic industry was used to determine optimum cost of production on the basis of Generally Accepted Accounting Principles.

## **H. Final Finding**

18. After considering the foregoing, the Authority concludes that:

- (a) Oxo alcohols (normal butanol, iso butanol, iso decanol, iso octanol 2-ethyl hexanol and normal hexanol only) originating in or exported from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and the European Union have been exported below normal value, resulting in dumping.
- (b) The Indian industry has suffered material injury.
- (c) The injury has been caused cumulatively by the dumped imports from the subject countries.

19. The Authority proposes to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed price of imports is proposed to be compared with the non injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigations.

20. The Authority recommends imposition of definitive anti dumping duty on import of subject goods in respect of subject countries/territories as per the amounts mentioned in the table below:

**Amount of duty recommended  
(US \$ Per MT)**

Country	Normal Butanol	Iso Butanol	2-Ethyl Hexanol & other Oxo- alcohols
Poland	44	165	165
South Korea	115	187	252
Russia	67	97	97
Iran	79	136	136
USA	58	NIL	87
European Union	145	204	121
Indonesia	197	194	197
Saudi Arabia	47	47	47

The amount of duty mentioned in the last column under the heading “2-Ethyl Hexanol and other Oxo Alcohols” is also applicable to Iso Decanol, Iso Octanol and Normal Hexanol. Wherever the particular form of Oxo Alcohol subject to investigation is not being imported from a particular subject country, residual rate of

duty has been recommended in the table given above on the basis of the data available on other forms of Oxo Alcohols being exported from that subject country.

21. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
22. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 3.12.99.
23. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, *supra*.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

